नीति से अभ्यास तक : एक कहानी उत्तराखण्ड से

अनन्त गंगोला और कैलाश चन्द्र काण्डपाल



आज हमारी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की बिगड़ती हुई हालत के बारे में हर जगह चर्चा होती ही रहती है और वह भी गहराई से विश्लेषण किए बिना। शिक्षा की स्थिति हर किसी को प्रभावित करती है अतः हर कोई इसके बारे में अपनी कोई-न-कोई राय रखता है। हमारे निर्णय अक्सर सतही होते हैं और हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कक्षा से लगाकर शैक्षिक नीतियों तक हमारी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली कितनी जटिल है।

इस प्रणाली के एक छोर पर कक्षा है, जो एक ऐसा स्थान है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपने साथ कई विविधताएँ लाता है जैसे अपनी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, अपना भावनात्मक और बौद्धिक स्वभाव, सीखने की अनुक्रिया और विभिन्न प्रकार की रुचियाँ, क्षमताएँ और सीमाएँ। यदि हम देश की शिक्षा प्रणाली पर विचार करें तो पाएँगे कि इसकी जटिलताएँ अति विशाल हैं जैसे राज्य और केन्द्रीय स्तर पर सचिवालयों, निदेशकों, परीक्षा बोर्डों की एक विशाल प्रणाली का निर्माण और प्रशासन; ज़िला और उप-ज़िला स्तर पर बुनियादी कार्यात्मक संरचनाओं का निर्माण; और स्थानीय स्वशासन, माता-पिता, शिक्षक समुदायों और स्कूल प्रबन्धन के साथ ज़मीनी स्तर पर जुड़ाव। संसद से लगाकर माता-पिता तक हर कोई किसी-न-किसी स्तर पर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सेदार है। जब हम शैक्षिक सुधारों की बात करते हैं तो इस विशाल प्रणाली की जटिलता और बड़े पैमाने को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।

अपनी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में एक नकारात्मक भावना के परिणामस्वरूप, हमने सबके लिए शिक्षा (एजुकेशन फॉर ऑल या ईएफए) और 'हर समाज में हर नागरिक' को शिक्षा के लाभ दिलाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय पहल को अपना लिया है और उन समुदायों के लाखों बच्चों को आमंत्रित किया है जो इतिहास में पहली बार स्कूल परिसर में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस प्रकार का प्रतिकूल वातावरण शिक्षकों और अन्य शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक है। इन कमियों की चिन्ता में हम इस क़दर डूब गए हैं कि अपनी शिक्षा प्रणाली के असाधारण प्रयासों और उपलब्धियों पर ध्यान ही नहीं दे रहे, जिसने 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने जैसी नीतियों को बनाए रखने के सभी प्रयास बड़ी नेकनीयती के साथ किए हैं। जब इसे अपनाया गया था तब शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन इस पहल को बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए गए थे। यह आलेख 2008-2010 के दौरान उत्तराखण्ड में किए गए एक महत्त्वपूर्ण प्रयास को प्रदर्शित करके हमारे देश में शिक्षा की स्थिति पर नकारात्मक चर्चा का प्रत्युत्तर देने की कोशिश करता है। हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए कि यह इस प्रकार का सिर्फ़ एक प्रयास है। देश के लगभग सभी हिस्सों में ऐसे बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं जिनके बारे में हम अनजान हैं और जिन्हें कोई मान्यता नहीं मिल पाती है।

शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता

यह एक ऐसे प्रयास का विवरण है जिसे उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के माध्यम से स्कूल की शिक्षा में दीर्घकालिक सुधार लाने के लिए किया गया। इसे समझने के लिए हमें राज्य स्तर पर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की संरचना को समझना होगा।

इसका संचालन एससीईआरटी के द्वारा होता है जो अनुसन्धान एवं विकास का कार्य करती है और स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों में राज्य शिक्षा विभाग को अकादमिक संसाधन सहायता प्रदान करती है। फिर नीतियों और प्रक्रियाओं के लिए क्रमशः सचिवालय और निदेशालय होते हैं। इसके अलावा परियोजनाओं के लिए कुछ इकाइयाँ और विभाग भी हैं जो प्रयासों को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। वैसे तो यह बात ज़रूरी है कि ये सभी संस्थाएँ आपस में बहुत निकटता के साथ सहयोग करें लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। इसलिए अगर इनको एक साथ लाना हो तो इसके लिए राजतंत्र और अधिकारी-तंत्र के स्तर पर प्रतिबद्धता का होना एक मूलभूत आवश्यकता है।

2008-2010 के दौरान उत्तराखण्ड में इस तरह की वांछित स्थिति देखने में आई थी। स्कूल शिक्षा के तत्कालीन सचिव डॉ. राकेश कुमार ने प्रणाली को सुधारने के लिए कई रणनीतियाँ सुझाईं। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षकगण स्कूल की औपचारिक व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अग्रदूत की भूमिका निभाते हैं। भारतीय सन्दर्भ में अपर्याप्त और ख़राब

शिक्षक-शिक्षा पर हमेशा से ही उँगली उठाई जाती रही है। शिक्षकों के निरन्तर व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षक-शिक्षा और सेवाकालीन कार्यक्रमों के प्रावधानों में प्रभावी निष्पादन की कमी है जो केवल अधिकारी-तंत्र से आ सकता है क्योंकि हमारी प्रणालियाँ ऐसे ही चलती हैं। डॉ. राकेश कुमार ने इस बात को पहचाना और महसूस किया कि यदि वे 'शिक्षक तैयारी' के मुद्दे को हल कर दें तो वे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर एक क़दम आगे बढ़ पाएँगे।

उत्तराखण्ड राज्य वर्ष 2000 में गठित किया गया था। अतः उसे उत्तर प्रदेश, जिसका वह अब तक हिस्सा था, से 'प्राथमिक शिक्षा का सेवा-पूर्व शिक्षक' विरासत में मिला। देश में शिक्षकों के लिए शिक्षक-तैयारी का एक बुनियादी पाठ्यक्रम था, विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए जिसे अब प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ़) 2005 की शुरुआत और तदनन्तर शिक्षक-शिक्षा का तालमेल इसके साथ बैठाने के लिए इसे संशोधित करने की बातचीत के कारण बाद में शिक्षक-शिक्षा (एनसीएफ़टीई) 2009 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनी। इसका असर सेवा-पूर्व शिक्षक-शिक्षा पर होना लाज़मी था। ऐसे समय में डॉ. राकेश कुमार ने बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (बेसिक ट्रेनिंग सर्टीफिकेट या बीटीसी) पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने का प्रयास किया। एससीईआरटी ने इसकी अगुआई की क्योंकि उसने शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार करने के महत्त्व को समझ लिया था। अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन (आगे इसे फ़ाउंडेशन के नाम से नामित किया जाएगा) को इस प्रयास के सुगमीकरण का कार्य सौंपा गया था।

चूँकि तब तक एनसीएफ़टीई 2009 लागू नहीं किया गया था इसलिए पाठ्यक्रम में बदलाव के आधार निम्नलिखित थे :

एक अच्छे शिक्षक में ये बातें होती हैं :

- विषय का ज्ञान और समझ
- विषय के लिए विशिष्ट शैक्षणिक (शिक्षण) कौशल
- शिक्षण-अधिगम के संसाधनों तक पहुँचने/विकसित करने की क्षमता
- शिक्षार्थियों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान
- समाज, शिक्षा और बच्चों की परिकल्पना और समझ

जिन परिवर्तनों को महत्त्वपूर्ण समझा गया वे इस प्रकार थे :

- नए शिक्षक अपने पेशे में परिकल्पना, योग्यता और प्रेरणा के साथ प्रवेश करते हैं जो शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल हैं।
- कार्यरत शिक्षकों को पेशेवर विकास कार्यक्रम अर्थपूर्ण लगते हैं।
- शिक्षक की तैयारी, विकास और अनुसमर्थन के प्रतिमानों में पूरी तरह से बदलाव आया है।

शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक अलग दृष्टिकोण

इन बातों को व्यवहार में कैसे लाया गया, इसकी कहानी बड़ी महत्त्वपूर्ण है।

इस कार्य के लिए राज्य से लगभग 30 संसाधकों की एक कोर टीम का चयन किया गया था। इस टीम में शिक्षकों से लगाकर वरिष्ठ शिक्षा कार्यकर्ताओं के विभिन्न अनुभवों वाले संसाधक तक शामिल थे। इस समूह ने शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम का पुनर्निर्माण और उसे पुनर्जीवित करने के तरीक़ों पर विचार-मन्थन किया। यह टीम आस-पास उपलब्ध विचारों का पता लगाने को तत्पर थी और फ़ाउंडेशन ने एकलव्य, दिगन्तर और विद्या भवन जैसे प्रमुख संगठनों के संसाधकों द्वारा समूह के अभिमुखीकरण की सुविधा प्रदान की। इस समूह ने नव निर्मित राज्य छत्तीसगढ़ द्वारा अपने डीएलएड के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के प्रयासों पर भी नज़र रखी।

कोर ग्रुप ने पहले के पाठ्यक्रम की समीक्षा की, सुझाव दिए और एनसीएफ़ 2005 के साथ इसका तालमेल बैठाने के लिए बदलाव किए। गहन बहसें और चर्चाएँ हुईं क्योंकि कुछ सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के पूर्व बीटीसी पाठ्यक्रम को उपयोगी पाया और इसमें संशोधन करने का सुझाव दिया, जबकि दूसरा वर्ग चाहता था कि एनसीएफ़ 2005 को ध्यान में रखते हुए पूरे पाठ्यक्रम को पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया जाए। बहस और चर्चाओं के बाद दूसरे समूह की बात मानी गई। इसका कारण एससीईआरटी का तत्कालीन नेतृत्व हो सकता है जिसका नेतृत्व अतिरिक्त निदेशक, एन.एन.पी. पाण्डे की अध्यक्षता में किया गया था, जो पूर्ण अकादमिक सटीकता के साथ कार्य करते थे और उनके पास वह दृष्टि भी थी जो वांछित उद्देश्यों की ओर केन्द्रित पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक है। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया। उत्तराखण्ड परीक्षा बोर्ड के साथ एक क़रीबी तालमेल बिठाया गया था ताकि यह भी नवीनीकृत पाठ्यक्रम के साथ मेल खा सके।

पाठ्यचर्या विकसित होने में लगभग एक वर्ष लग गया। अलग-अलग समूहों ने विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों को लिया-शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से विषयों की प्रकृति तक। यह निर्णय लिया गया कि व्याख्यान शामिल न किए जाएँ। पाठ्यपुस्तक नहीं रखने के पक्ष में भी सोच-समझकर निर्णय लिया गया। इसलिए यह कक्षा-अभ्यास की दिशा में एक अलग दृष्टिकोण था।

पाठ्यचर्या से अभ्यास तक

पाठ्यक्रम के तैयार होने के बाद बुनियादी सुविधाओं और मानव संसाधनों के लिए ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में सक्षम स्थितियों को तैयार करने की आवश्यकता थी ताकि पाठ्यक्रम को उचित तरीक़े से अमल में लाया जा सके। उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और मानव संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए डाइट का सर्वेक्षण किया गया। उस समय राज्य में दस डाइट और तीन ज़िला संसाधन केन्द्र (डीआरसी, जिसे 'मिनी डाइट' भी कहा जाता था) थे और यह पाया गया कि प्रत्येक में बुनियादी सुविधाओं और मानव संसाधनों की कमी थी। एक विश्लेषण यह पता लगाने के लिए किया गया कि डाइट के पास क्या कोई ऐसी धन राशि उपलब्ध है जिसका उपयोग बुनियादी सुविधाओं सम्बन्धी मुद्दों को हल करने के लिए किया जा सके। फ़ाउंडेशन ने इस विश्लेषण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। निदेशालय को संस्थानों में वांछित मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया था। कुछ ही समय में सभी संस्थानों को काफ़ी बेहतर बुनियादी सुविधाएँ और मानव संसाधन प्राप्त हुए। बुनियादी सुविधाओं में नवीनतम तकनीकें शामिल थीं जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन और एलसीडी प्रोजेक्टर। पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की एक सूची सुझाई गई और फ़ाउंडेशन ने सभी डाइट और डीआरसी को इनमें से कुछ किताबें उपलब्ध कराईं ताकि परिवर्तित पाठ्यक्रम में सुचारु रूप से परिवर्तन हो सके।

चूँकि पाठ्यचर्या के साथ-साथ अध्यापन पद्धति के प्रतिमान में भी बदलाव आया था इसलिए संस्थानों के प्रमुखों और संकाय का उन्मुखीकरण करना आवश्यक था। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संस्थानों के प्रमुखों का आवश्यक प्रशासनिक और अकादमिक कार्यों के सम्बन्ध में उन्मुखीकरण किया गया जो व्यापक रूप से निम्नलिखित श्रेणियों पर आधारित था :

- प्रबन्धन और योजना
- संकाय के साथ समन्वयन
- पाठ्यचर्या के अमल की निगरानी
- साप्ताहिक इन-हाउस बैठकें
- एससीईआरटी को फीडबैक- प्रशासनिक और अकादमिक
- संसाधन सहायता
- सम्पर्क कार्य
- प्रशिक्षण का मूल्यांकन

इसके अलावा संकाय के कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिनकी नई-नई भर्ती हुई थी और जो पहले मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करते थे और उन्हें सेवा-पूर्व शिक्षक-शिक्षा में शिक्षण का अनुभव नहीं था। इसलिए प्रशिक्षण को सटीक और कठोर होना था और पाठ्यचर्या के अमल का निरन्तर फालोअप।

दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त एससीईआरटी में नेतृत्व बदल गया, लेकिन नए अतिरिक्त निदेशक, एन.सी. कबडवाल अपने पूर्ववर्ती निदेशक एन.एन.पी. पाण्डे के दृष्टिकोण से सहमत थे और उन्होंने पहले से चल रहे प्रयासों को वांछित दिशा में आगे बढ़ाया। उन्होंने उन्मुखीकरण के कार्यक्रमों के सुचारु संचालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और अधिकांश सत्रों के सुगमीकरण के लिए वे स्वयं उपस्थित रहते थे। हर क्षेत्र के प्रत्येक डाइट से संकाय के एक कोर समूह का एक सप्ताह के लिए उन्मुखीकरण किया गया और फिर उन्हें अपने संस्थान में बाकी के डाइट संकाय के उन्मुखीकरण का कार्य सौंपा गया।

चूँकि पूरी प्रक्रिया कुछ हद तक परिवर्तनवादी थी इसलिए यह कोशिश भी की गई कि बदलाव को लेकर उत्साह बना रहे। डाइट में उत्सव का एक ऐसा माहौल बनाया गया कि बीटीसी कोर्स के उम्मीदवार नए पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्साहित हों। उम्मीदवारों का स्वागत करने के लिए बैनर लगाए गए और कुल मिलाकर विद्यार्थी इस कोर्स में भाग लेने के लिए उत्साहित थे।

डाइट और डीआरसी में इस संशोधित पाठ्यक्रम के अमल की समीक्षा करने के लिए कुशल योजना भी थी। एक टीम बनाई गई जिसमें एससीईआरटी और फ़ाउंडेशन से एक-एक सदस्य को शामिल किया गया। इस टीम ने डाइट और डीआरसी का दौरा किया। इस टीम ने कक्षाओं का अवलोकन किया और संकाय व विद्यार्थी-प्रशिक्षुओं के साथ बैठकें कीं। बाद में ये सभी टीमें राज्य स्तर पर एक साथ बैठीं और विभिन्न पहलुओं, जैसे इन संस्थानों में संसाधनों की उपलब्धता से लेकर पाठ्यक्रम के अमल तक, के बारे में अपने अनुभव साझा किए। इससे विभिन्न स्थानों पर पाठ्यक्रम के अमल के अच्छे तरीक़ों पर प्रकाश डालने और साझा करने में भी मदद मिली।

विभिन्न हितधारकों ने भी कई प्रकार की प्रतिक्रियाएँ दिखाईं। शुरू में शिक्षकों को पाठ्यक्रम और अध्यापन में आए बदलाव के साथ अनुकूलन करने में मुश्किल हुई। ईमेल द्वारा सभी संस्थानों और प्रमुख लोगों को जोड़कर लगातार सहायता और पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। एससीईआरटी, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट से भी बहुत मदद मिली क्योंकि इसमें डीएलएड के संशोधित पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक सामग्री थी। इस दौरान कुछ अभिनव प्रथाएँ भी उभरीं जिनमें बाहरी संसाधकों को बुलवाना, संस्थानों के भीतर संसाधन जुटाना और विद्यार्थी-प्रशिक्षुओं की विशेषज्ञता का उपयोग करना आदि उल्लेखनीय हैं।

अब यह भी स्पष्ट हो गया था कि संकाय को निरन्तर सहायता की आवश्यकता है और इसलिए क्षेत्रीय संसाधन समूह (आरआरजी) का विचार उभरा। विषयवार आरआरजी का गठन किया गया जिसमें डाइट, एससीईआरटी और फ़ाउंडेशन के विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया। उत्तराखण्ड के दोनों क्षेत्रों यानी कुमाऊँ और गढ़वाल के आरआरजी सेमेस्टर के अन्त में अपने सम्बन्धित स्थानों पर मिले और सेमेस्टर की समीक्षा की तथा अगले सेमेस्टर के लिए योजना बनाई। यह विचार काफ़ी कारगर साबित हुआ क्योंकि इससे अलग-अलग स्थानों में जो भी अच्छा काम हो रहा था, उसे साझा करने में मदद मिली। चूँकि पाठ्यक्रम विकास के दौरान उत्तराखण्ड परीक्षा बोर्ड के साथ जुड़ाव हुआ था, इसलिए इसी तर्ज़ पर मूल्यांकन में भी सुधार किए गए जैसे कि सूचना पर कम और सीखने, पाठ्यक्रम की समझ और अनुप्रयोग पर अधिक बल देना।

पाठ्यक्रम का मूल्यांकन

पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो जाने के कारण विद्यार्थी परीक्षाओं को लेकर कुछ चिन्तित थे और उनके मन में अनिश्चितता भी थी। लेकिन पहले सेमेस्टर की परीक्षा होने के बाद जब उन्होंने मूल्यांकन के संशोधित तरीक़े देखे तो उन्हें भी वे दिलचस्प लगे। 2011-12 में फ़ाउंडेशन द्वारा इस विषय पर एक अध्ययन किया गया था जिसका उद्देश्य बदलते पाठ्यक्रम की स्थिति को समझना और सम्बन्धित शैक्षिक हितधारकों के अनुभवों का विश्लेषण करना था। रिपोर्ट में बताया गया कि संशोधित पाठ्यक्रम तथा एनसीएफ़ 2005 और एनसीएफ़टीई 2009 में तालमेल है। हितधारकों ने निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष दिए :

- विद्यार्थी-प्रशिक्षुओं, विशेष रूप से शिक्षा-मित्रों (पैरा-टीचर्स) ने, ख़ासतौर पर यह कहा कि बाल मनोविज्ञान को समझने की दिशा में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या सीडब्ल्यूएसएन), बहुकक्षा व बहुस्तरीय (मल्टी-ग्रेड मल्टी लेवल या एमजीएमएल) और नैतिक शिक्षा और संस्कृत जैसे विषयों के लिए शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं पर कोई चर्चा नहीं हुई। गणित के पाठ्यक्रम में दी गई सामग्री का स्तर प्राथमिक कक्षाओं के स्तर से कहीं अधिक था।

- सभी प्रधानाचार्य, डाइट और डीआरसी के प्रभारीगण पाठ्यक्रम से काफी सन्तुष्ट थे। उनमें से कुछ ने पाठ्यक्रम को बहुत प्रभावी पाया क्योंकि यह सैद्धान्तिक नहीं वरन व्यावहारिक था और यह बात पिछले (छह महीने के विशेष बीटीसी) पाठ्यक्रम के विपरीत थी। उन्हें यह बात भी पसन्द आई कि नए पाठ्यक्रम में एक अच्छे शिक्षक के गुणों पर ध्यान दिया गया था जैसे कि शिक्षक को स्कूल में कैसे पढ़ाना चाहिए, शिक्षण को दिलचस्प कैसे बनाया जाए और बच्चों के साथ बातचीत कैसे की जाए। डाइट संकाय को पाठ्यक्रम की सेमेस्टर-वार संरचना भी पसन्द आई।

- पाठ्यचर्या बनाने वाले दल का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि पाठ्यक्रम में सामग्री की बजाय अन्तःक्रियात्मक प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाए। पाठ्यक्रम में 'विषय की प्रकृति' वाली अवधारणा (यानी सामग्री पर अधिक ध्यान देने वाली अवधारणा में बदलाव) की शुरुआत बहुत फ़ायदेमन्द रही। इससे विद्यार्थी-प्रशिक्षुओं को अपने विषयों को बेहतर रूप से समझने में मदद मिली।

- पाठ्यचर्या बनाने वाले दल ने यह भी महसूस किया कि पाठ्यक्रम दार्शनिक दृष्टिकोण से तो अच्छा था लेकिन यह व्यावहारिक नहीं था क्योंकि इसमें वास्तविक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया था। एक और समस्या यह थी कि विद्यार्थियों की बड़ी संख्या के कारण पाठ्यक्रम और गतिविधियों को पूरी तरह से नहीं किया जा सका।

- डाइट संकाय ने महसूस किया कि पाठ्यक्रम का मुख्य गुण यह था कि इसमें विद्यार्थी-प्रशिक्षुओं को इस बात की स्वतंत्रता थी कि वे अपने विचार व्यक्त कर सकें, समूह चर्चाओं और प्रस्तुतियों में भाग ले सकें और दूसरों को भी सुन सकें।

संस्थागत स्तर पर यह रिपोर्ट बहुत उत्साहजनक नहीं है। बुनियादी सुविधाओं और मानव संसाधनों को लेकर अभी भी चुनौतियाँ थीं। दूसरे, इन शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के नेतृत्व में बार-बार परिवर्तन होता रहा जिससे बदलाव की प्रक्रिया प्रभावित हुई। शिक्षक-शिक्षा संस्थान के पुस्तकालयों में इतनी पुस्तकें नहीं थीं जो शिक्षकों की माँग पूरी कर सकें। एक चुनौती यह भी थी कि शुरुआती चरण में डाइट संकाय के सदस्यों में उत्साह की कमी देखी गई क्योंकि उन्हें बदले हुए पाठ्यक्रम की सीमित जानकारी थी। इंटर्नशिप जैसे पाठ्यक्रम के कुछ पहलू पूर्ण रूप से लागू नहीं किए जा सके। संसाधनों की कमी के मूल कारणों में से एक कारण यह भी था कि प्रत्येक डाइट में जितने विद्यार्थी-प्रशिक्षुओं को नियत किया गया था, उनकी संख्या बहुत अधिक थी।

रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक-निजी भागीदारी ने पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे ऑन-साइट सहायता, संकाय की चुनौतियों को समझने और मुद्दों को सुलझाने के लिए आरआरजी की बैठकों के आयोजन में सहायता मिली। सभी डाइट संकाय सदस्यों के 'विज़न' के

लिए विशेष प्रावधान करना, प्रत्येक संस्थान को विषय-सामग्री प्रदान करना आदि कुछ ऐसे प्रमुख बिन्दु थे जहाँ फ़ाउंडेशन ने डाइट को समय पर सहायता प्रदान की।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकार ने सभी विभागों और हितधारकों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप अब राज्य में संशोधित पाठ्यक्रम स्थापित हो गया है। उत्तराखण्ड की यह कहानी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अगर अधिकारी-तंत्र ईमानदारी के साथ भागीदारी करे और प्रतिबद्धता का पालन करे तो प्रणाली में महत्त्वपूर्ण बदलाव हो सकता है और जब आधारभूत कारणों पर उचित रूप से कार्यवाही की जाए तो परिवर्तन स्थायी रहता है।

संदर्भ :

1. *सेवा-पूर्व शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम की अवधारणा और कार्यान्वयन*, 2010-12. उत्तराखण्ड

अनन्त गंगोला वर्तमान में अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलूरु में कार्यरत हैं। वे बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों में अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन की फील्ड पहल का नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने 10 वर्षों से भी अधिक समय तक टीएलसी, डीपीईपी और एसएसए के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश सरकार के साथ भी काम किया है। उनसे *anant@azimpremjifoundation.org* पर सम्पर्क किया जा सकता है।

कैलाश चन्द्र काण्डपाल वर्तमान में अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन, उत्तराखण्ड के राज्य प्रमुख हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में भी काम किया है और अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन में शामिल होने से पहले वे उत्तराखण्ड के शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। उनसे *kandpal@azimpremjifoundation.org* पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** नलिनी रावल